



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686 ]  
No. 686]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 1996/अग्राहायण 6, 1918  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 1996/AGRAHAYANA 6, 1918

गृह मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1996

का. आ. 823(अ).—यतः नेशनल सोशलिस्ट कार्टिसिल आफ नागालैंड और विभिन्न नेताओं के नेतृत्व में इसके सभी गुट, विंग और अग्रिम संगठन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् एन एस सी एन कहा गया है) और एनएससीएन या उसकी ओर से या उसके नाम से कार्य करने के लिए तात्पर्यित अभिकरण :—

- (1) नागा आबादी वाले क्षेत्रों को, जो भारतीय प्रदेश का अंग है, संघ से विलग करने के अपने नीतिगत उद्देश्यों की घोषणा करता है;
- (2) ऐसी विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त रहा है जो भारत की प्रभुता एवं अखंडता के प्रतिकूल है;
- (3) अपने उद्देश्यों के अनुसरण में उस अवधि के दौरान, जब इसे एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया था, अनेक विधि विरुद्ध तथा हिंसात्मक गतिविधियों में संलिप्त रहा है जिसके कारण विधि सम्मत स्थापित सरकार के प्राधिकार का क्षरण हुआ है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों में आतंक और हिंसा फैलायी है।

और यतः केन्द्रीय सरकार का आगे यह मत है कि हिंसात्मक तथा विधि विरुद्ध गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

- (क) सिविलियनों और पुलिस तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों की बड़े पैमाने पर हत्या;
- (ख) नागालैंड, मणिपुर और असम तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में व्यापारियों, व्यवसायियों और सरकारी अधिकारियों समेत जनता से धन ऐंठना और अवैध कर वसूली करना;
- (ग) उल्फा, बोडो उग्रवादियों, मैतेयी, त्रिपुरा और खासी उग्रवादी ग्रुपों जैसे पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही ग्रुपों के साथ संपर्क कायम करना और उन्हें मजबूत बनाना एवं उन्हें समर्थन प्रदान करना;
- (घ) पड़ोसी देशों में शरण स्थल, सुरक्षित ठिकाने और प्रशिक्षण केन्द्र कायम करना;
- (ङ) विदेश में गुप्त/अवैध माध्यमों से अत्याधुनिक हथियारों समेत बड़ी संख्या में हथियार और गोली बारूद प्राप्त करना और कुछ पड़ोसी देशों के जरिए उन्हें गुप्त रूप से मणिपुर तथा नागालैंड में पहुंचाना;
- (च) विदेशों में भारत-विरोधी प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और "द वर्किंग ग्रुप आन इंडीजीनियस पीपल्स" आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग करना;

(छ) शांति के लिए सभी पहलों, शांतिवार्ता के प्रस्तावों को अस्वीकार करना;

(ज) मणिपुर और नागालैंड में नागा और कुकी समुदायों के बीच साम्प्रदायिक संघर्ष को सुलगाना ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि पूर्वोक्त कारणों से एन एस सी एन एक विधि विरुद्ध संगठन है;

इसलिए अब विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (एन एस सी एन) को उसके सभी गुटों, विंगों तथा अग्रिम संगठनों सहित विधि विरुद्ध संगम घोषित करती है;

और यतः केन्द्रीय सरकार का आगे यह मत है कि यदि तत्काल कोई अंकुश और नियंत्रण न लगाया गया तो यह—

- (1) अपनी अलगाववादी, विध्वंसकारी और आतंकवादी/हिंसात्मक गतिविधियों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने;
- (2) भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता के प्रति वैमनस्य रखने वाली ताकतों से मिलकर खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों का प्रचार करने;
- (3) सिविलियनों की और अधिक हत्याएं करने और पुलिस तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों को निशाना बनाने;
- (4) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से और अधिक अवैध हथियार और गोलाबारूद प्राप्त करने और प्रविष्टि कराने;
- (5) विदेशी एजेंसियों की मिली भगत से विदेशों में भारत-विरोध प्रचार का स्तर बढ़ाने;
- (6) अपनी विधि विरुद्ध गतिविधियों के लिए लोगों से भारी मात्रा में धनराशि ऐंठने और अवैध कर वसूल करने का अवसर प्राप्त कर लेगा ।

उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार का यह दृढ़ मत है कि एन एस सी एन और इसके गुटों, विंगों तथा अग्रिम प्रभाव से, विधि विरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार उक्त धारा 3 की उप-धारा 3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निर्देश देती है कि अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किए जा सकने वाले किसी आदेश के अध्यक्षीन सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 7/21/96-एन.ई. 1]

जी० के० पिल्ले, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1996

**S. O. 823(E) :—**Whereas, the National Socialist Council of Nagaland, and all factions, wings and front organisations thereof under various leaders (hereinafter referred to as NSCN) and the agencies purporting to act in or behalf of the NSCN or in its name :—

- (1) has been declaring as its policy objectives of secession of the Naga inhabited areas, a part of the territory of India, from the Union;
- (2) has been engaging in unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;
- (3) in pursuance of its aims and objectives engaged in several unlawful and violent activities during the period when it had been declared as unlawful association, thereby undermining the authority of the lawfully established government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives.

And whereas, the Central Government is further of the opinion that violent and unlawful activity include—

- (a) large scale killing of civilians and personnel belonging to the police and security forces;
- (b) extortion of funds and collection of illegal tax from the public including businessmen, traders and government officials in Nagaland, Manipur and parts of Assam and Arunachal Pradesh;
- (c) maintaining and further strengthening links with the other North-East insurgent groups like the ULFA, Bodo militants, Meitei, Tripura and Khasi extremist groups and extending support to them;

- (d) maintaining sanctuaries, safe havens and training camps in the neighbouring countries;
- (e) procuring large number of arms and ammunition, including sophisticated ones, through clandestine/illegal channels abroad and induct them secretly into Manipur and Nagaland through some neighbouring countries;
- (f) utilising international fora like the UN Commission on Human Rights, the Working Group on Indigenous peoples etc. for anti-Indian propaganda abroad;
- (g) rejection of all peace initiatives and offers of peace talks;
- (h) extending active support to Naga villagers for causing and fomenting communal clashes between the Nagas and Kuki tribals in Manipur and Nagaland.

And whereas the Central Government is of the opinion that for the aforesaid reasons the NSCN is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967); the Central Government hereby declares the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) including all its factions, wings and front organisations as unlawful associations;

And whereas the Central Government is further of the opinion that if there is no immediate curb and control, it will take the opportunity to—

- (1) mobilise its cadres for escalating its secessionist, subversive and terrorist/violent activities;
- (2) openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;
- (3) indulge in increased killings of civilians and targetting of police and security forces personnel;
- (4) procure and induct more illegal arms and ammunition from across the international borders;
- (5) raise the level of anti-India propaganda abroad in connivance with foreign agencies;
- (6) extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities.

Having regard to the above circumstances, the Central Government is of the firm opinion that it is necessary to declare the NSCN, and all its factions, wings and front organisations thereof as unlawful associations with immediate effect; and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section 3 of the said Section 3, the Central Government directs that the notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 7/21/96—NE.I]

G.K. PILLAI, Jt. Secy.

